कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1990–95 में कोई आयात नहीं हुआ । 1991–92 से 1994–95 तक का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	वाणिज्यिक दुग्ध चूर्ण		आयात बटर आयल		विश्व खाद्य कार्यक्रम बटर आयल		यूरोपीय आर्थिक समुदाय खाद्य सहायता (दुग्ध चूर्ण)	
	मात्रा (मीं० टन)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (मीं० टन)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (मीं० टन)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (मीं० टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1991-92	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3004	1669	शून्य	--
1992-93	2602	1403	शून्य	शून्य	2144	1133	1194	4272
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	--	3000	1076
1994-95	शून्य	शून्य	4305	3634	शून्य	--	शून्य	--

(ख) और (ग) आरक्षित फण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त उपहार उपभोज्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य का उपयोग परियोजना के क्रियान्वयन के लिये किया जाता है । बटर आयल का विक्रय मूल्य विश्व खाद्य कार्यक्रम को उनके कार्यक्रमों में क्रियान्वित करने के लिये हस्तांतरित कर दिया गया था। वाणिज्यिक आयातों के सकल मूल्य का उपयोग ऐसे आयातों के व्यय के लिये किया जाता है तथा इस प्रकार के खर्चों को पूरा करने के पश्चात अधिशेष का उपयोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना

6557. **प्रो. राम बक्श सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां । चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये प्रस्ताव भेजा है ।

(ग) और (घ) जी, हां । प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 1993 में जारी की जा चुकी है ।

गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और उनके वितरण में असंतुलन

6558. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन तथा वितरण में काफी असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;

(ग) इन असंतुलनों के लिये कौन-कौन से तंत्रों को दोषी पाया गया है ; और

(घ) उनमें सुधार लाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Financial assistance to cooperative societies by NCDC

6559. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the financial assistance provided to cooperative societies by the National Cooperative Development Corporation for promoting the trade of consumer goods in the tribal and rural areas of the country, State-wise;

(b) whether the National Cooperative Development Corporation has made any review of the performance of these cooperative societies; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) A statement-Indicating the State/Union Territory-wise release of financial assistance made by the National Cooperative Development Corporation (NCDC) upto 31-3-94 under its Rural Consumer Scheme to Cooperative Societies for promoting trade of consumer goods in rural and tribal areas is enclosed. (*See* below).

(b) and (c) The National Cooperative Development Corporation commissioned Council for Rural and Cooperative Development (CRCD) to undertake a study of their Rural Consumer's Scheme in 1990 in the States of Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and West Bengal. The recommendations made in the study were communicated to these states and other concerned organisations in 1991 for evolving suitable measures for improving the operational performance of the cooperatives in rural consumer business. Main recommendations of the study are given in Statement-II. (*See* below) Another study had also been commissioned by NCDC for Tamil Nadu and Madhya Pradesh in 1994. The report of this study has been received by NCDC on 21-4-95 and the findings of the study are being examined by the NCDC.

Statement—I

Assistance provided by NCDC for promoting trade of consumer goods.

Sl. No.	State U/T	Cumulative assistance provided upto 31-3-94		
		In Rural Area	In Tribal Areas	Total
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	267.41	32.85	300.29
2.	Assam	70.90	24.63	95.53
3.	Bihar	284.03	11.78	295.81
4.	Goa	7.66	..	7.66